



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050



+918988886060

www.vajiraoinstitute.com



info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(वर्ष का लेखा-जोखा)

(December 2023)

(Part II)

TOPICS TO BE COVERED

- आवागमन का पुनर्निर्धारण: भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव
- अंतरिक्ष में भारत की ऊँची उड़ान

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



आवागमन का पुनर्निर्धारण: भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव

परिचय:

- परिवहन की एक सुव्यवस्थित और समन्वित प्रणाली किसी देश की निरंतर आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटीय शिपिंग, हवाई परिवहन आदि सहित परिवहन के कई तरीके शामिल हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में परिवहन ने नेटवर्क के प्रसार और सिस्टम के आउटपुट दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है।
- नौवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय परिवहन के विभिन्न तरीकों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।



सड़क परिवहन:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था।

ADDRESS:



- सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष संगठन है।
- यातायात (यात्री और माल) को संभालने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में लगभग 62.16 लाख कि.मी. सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है।

भारतमाला परियोजना:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने *भारतमाला परियोजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने, गैर प्रमुख चंद्रगाहों के लिए सड़क कनेक्टिविटी सहित तटिय सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों को क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारों के विकास, अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के विकास आदि के साथ-साथ सागरमाला के साथ एकीकरण की दृष्टि से एनएच नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है।*
- भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 कि.मी. लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें **स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर-**

ADDRESS:



दक्षिण और पूर्व-पश्चिम (एनएस ईडब्ल्यू) गलियारों के साथ-साथ सड़कों पर अधिकांश माल ढुलाई की संभावना है।

- इस कार्यक्रम में शहरों से गुजरने वाले यातायात को कम करने और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए रिंग रोड/बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास इत्यादि की परिकल्पना की गई है।

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना:

- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना 2016 में शुरू की गई थी। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है।
- इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले सभी 781 किलोमीटर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन शामिल है।
- इसे हरित राजमार्ग नीति के तहत लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करना, क्योंकि वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करने में पेड़ों और झाड़ियों को वायु प्रदूषकों के अवशोषण का एक प्राकृतिक घटक माना जाता है, वाहनों को संख्या में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, तटबंध के ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकना, आदि परियोजना के उद्देश्यों में शामिल हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना एनएचएआई अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी।
- इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अन्य छोटी परियोजनाओं के साथ, 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अनुबंध आवंटन और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के अनुरूप हों, परियोजनाओं का कार्यान्वयन सर्वोत्तम गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप हों, और राजमार्ग प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका रखरखाव करना सुनिश्चित हो।
- देश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एक्सप्रेसवे सहित) की कुल लंबाई 1,32,499 किमी है। जबकि राजमार्ग/एक्सप्रेसवे सभी सड़कों की लंबाई का लगभग 1.7 प्रतिशत ही हैं, किंतु वे सड़क यातायात का लगभग 40 प्रतिशत वहन करते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना:

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) देश में प्रमुख राजमार्गों के उच्च मानक तक उन्नत, पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की एक परियोजना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी।
- यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 49,260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के काम और निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। एनएचडीपी को मौजूदा भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया है।

पीएम गति शक्ति योजना:

- पीएम गति शक्ति, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, 2021 मूल रूप से आधारभूत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है।
- इससे आधारभूत सुविधाओं को अंतिम दूरी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और लोगों के लिए यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा।

पर्वतमाला परियोजना:

- यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे के विकास के लिए पर्वतमाला परियोजना-राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ, **वाराणसी, उज्जैन जैसे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों** में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में रोपवे विकसित किए जा रहे हैं।

नौवहन मंत्रालय:

- नौवहन मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था।
- समुद्री परिवहन किसी देश के **आर्थिक विकास** के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा है।
- 2020 में मंत्रालय का नाम बदलकर पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया।
- मंत्रालय **अपने दायरे में नौवहन और बंदरगाह क्षेत्रों को शामिल करता है, जिसमें जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल हैं।**
- यह **नौवहन से संबंधित नियमों और विनियमों तथा कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है।**
- विदेशी व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके **बर्थ और कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के संदर्भ में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में काफी सुधार हुआ है और वर्तमान में इसकी क्षमता 1617.39 एमएमटी है।**

ADDRESS:



समुद्री विकास:

- भारत का लगभग 7517 किमी. लंबा समुद्र तट है, जो मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी शेल्फ और द्वीपों के साथ-साथ फैली हुई है।
- यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
- यहां 12 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
- देश का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार मात्रा के हिसाब से और 68 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है।

सागरमाला कार्यक्रम:

- समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर के संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करने के लिए, भारत सरकार ने देश में पोर्टेड विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं के निवेश के साथ आयात-निर्यात और घरेलू व्यापार की रसद लागत को कम करना है।
- कार्यक्रम के उद्देश्यों में बंदरगाह का आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी, तटीय सामुदायिक विकास आदि शामिल हैं।

ADDRESS:



प्रमुख बंदरगाह:

- उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं।
- बंदरगाह समुद्री परिवहन और भूमि-आधारित परिवहन के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 205 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।**
- **प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और संघ सूची (संविधान की 7वीं अनुसूची) में शामिल हैं।**
- प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह संबंधित समुद्री राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और समवर्ती सूची में शामिल हैं।
- सभी **भारतीय बंदरगाहों द्वारा प्रबंधित कुल यातायात का, 55 प्रतिशत प्रमुख बंदरगाहों द्वारा और 45 अन्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है।**

अंतर्देशीय जल परिवहन:

- भारत में लगभग 14,500 किमी लंबा नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- अंतर्देशीय जल परिवहन एक ईंधन-कुशल, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती तथा कम कार्बन उत्सर्जन वाला परिवहन का माध्यम है।
- हालांकि, इसके माध्यम से माल परिवहन वर्तमान में देश में कुल माल परिवहन का 2 प्रतिशत से भी कम है।
- सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 24 राज्यों में फैले 111 (5 मौजूदा और 106 नए सहित) राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) को घोषणा की।
- विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी खंड पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की क्षमता वृद्धि के लिए आईडब्ल्यूआई द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित की जा रही है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान की परिकल्पना राष्ट्रीय उड़डयन नीति 2016 में की गई थी।
- आरसीएस-उड़ान का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के

ADDRESS:



प्रशासन और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा रियायते जैसे उपाय करना है और ऐसे मार्गों पर एयरलाइन संचालन को पूरा करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीवीएफ) का प्रावधान करके जनता के लिए इसे किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाना है।

- पहली आरसीएस-उड़ान की उड़ान का शुभारंभ 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए किया गया था।
- 2016 में उड़ान के लॉन्च होने तक, भारत में निर्धारित परिचालन वाले 74 हवाई अड्डे थे, जबकि योजना के शुरू होने के बाद पिछले छह वर्षों के दौरान, विभिन्न एयरलाइनों को 1,300 वैध मार्ग प्रदान किए गए हैं, 75 असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों (1 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे सहित) को जोड़ने वाले 495 मार्ग (10 अक्टूबर 2023 तक) चालू हो गए हैं।

कृषि उड़ान 2.0:

- कृषि उड़ान 2.0 योजना भारतीय मालवाहक और यात्री से कार्गो के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज (टीएनएलसी), और रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान करके हवाई परिवहन द्वारा कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में शुरू की गई थी।

ADDRESS:



- चयनित हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र और द्वीपों और अन्य चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- इस योजना में देश के कुल 58 हवाई अड्डे शामिल हैं। पहचाने गए कुल 58 हवाई अड्डों में से 25 पूर्वोत्तर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों में और 33 हवाई अड्डे अन्य क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं।

सुगम्य भारत अभियान:

- सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, नागर विमानन मंत्रालय ने लोगों को व्यापक पहुंच मानकों को समझने में सहायता करने के लिए 'नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए पहुंच मानक और दिशानिर्देश' प्रकाशित किए हैं।
- हवाई यात्रा में पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इससे हवाई अड्डों पर पहुंच सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु *सेवारं प्रदान करने वाले लोगों को कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ लोगों, बच्चों, गर्भवती माताओं और विभिन्न अन्य उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हवाई यात्रा को सभी के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके।*

ADDRESS:



अंतरिक्ष में भारत की ऊँची उड़ान:

परिचय:

- 1960 के दशक के मध्य के उस दौर में जब विश्व भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष दौड़ में लगी थी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर केन्द्रित था।
- तभी से कार्यक्रम का विस्तार सामाजिक लाभ प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से हो रहा है।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने **इन-हाउस और भारी संसाधनों का व्यापक उपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, सामग्रियां और औद्योगिक प्रक्रियाए विकसित की हैं।**
- **विगत 50 वर्षों में प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के डिजाइन विकसित करके उनका निर्माण करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।**
- इसरो विश्व की उन पांच प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो गया, जिनके पास पृथ्वी के अध्ययन, संचार, नेविगेशन और ग्रह संबंधी खोजों की पूर्ण क्षमता है।



ADDRESS:



प्रक्षेपण यान:

- इसरो ने अपने किस्म की अनूठी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित कर ली है। वह अपने चार सक्रिय प्रक्षेपण यानों की सहायता से *पृथ्वी की निचली, मझौली और ऊंची कक्षा में 500 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक के पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है।*
- इसरो की **असली ताकत है पीएसएलवी** (ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान) जो 2 टन श्रेणी के पेलोड अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में दुनियाभर के कमर्शियल उपभोक्ताओं को इसका अत्यधिक भरोसेमंद और किफायती समाधान उपलब्ध कराता है।
- भारत में विकसित और निर्मित प्रक्षेपण यान **एलवीएम 3 में स्वयं को आवश्यकतानुसार एडजेस्ट करने की अद्भुत क्षमता है** और इसने चन्द्रयान तथा वनवेव कमर्शियल वाहनों के प्रक्षेपण जैसे जटिल मिशनों में अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
- छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान बाजार की ज़रूरतें पूरी करने के उद्देश्य से इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) रिकॉर्ड समय में विकसित किया है।

नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल प्रणालियां:

- इसरो ने काफी पहले ही सेंसर, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल प्रणालियों की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- *मून ऑर्बिटर मिशन और चन्द्रयान-3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों को सफलता का श्रेय इस अनूठी क्षमता को भी दिया जा सकता है।*
- देश में पूर्वी और दक्षिण दोनों मार्गों पर प्रक्षेपण के लिए इसरो को अपनी ग्राउंड, (जमीन) प्रणालियां हैं।
- मास्टर कंट्रोल सुविधा तथा ट्रेकिंग और टेलीमेट्री सुविधा से सभी ईओ, संचार नेविगेशन और वैज्ञानिक उपग्रहों पर चौबीसों घंटे निगाह रखी जाती है।

भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS):

- अपने संचालित नाम 'नाविक' से जानी जाने वाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली भारतीय तारामंडल के नेविगेशन की भूमिका निभाती है।
- यह प्रणाली *भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर के घेरे में भारत और इस क्षेत्र के लिए एकदम ठीक सही-समय वाली पोजिशनिंग और टाइमिंग (स्थिति और समय का आकलन) सेवाएं उपलब्ध कराती है।*
- नाविक से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं में यान ट्रेकिंग और फ्लीट प्रबंधन, मोबाइल फोनों में उपलब्ध लोकेशन आधारित सेवाएं, यात्रियों के लिए पृथ्वी संबंधी नेविगेशन सहायता, समय विभाजन, आपदा प्रबंधन और अन्य कई सेवाएं शामिल हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट:

- भारत को पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट 28 सितंबर, 2005 को लॉन्च को गई थी, 1515 किलोग्राम भार को यह वेधशाला को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी (XL) रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी।
- 54 देशों के करीब 2000 लोगों ने सितंबर 2022 में एस्ट्रोसैट डेटा इस्तेमाल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मार्स ऑर्बिटर मिशन:

- 5 नवम्बर, 2013 को मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। ग्रहों के बीच 300 दिन का सफर पूरा करने के बाद 24 सितंबर, 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था।
- 8 वर्ष के जीवनकाल वाले इस मिशन में कुल पांच वैज्ञानिक पेलोड भेजे गए थे, जिनसे हमें मंगल ग्रह के वातावरण (वायुमंडल), बाहरी वातावरण (एक्सोस्फीयर) और उसकी सतह की खूबियां तथा अन्य बातें जानने में बहुत मदद मिली।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)